जी. सी. मितल और एस. एस. ग्रेवाल, जे.जे. के समक्ष

जे.सी.मित्तल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 7864।

12 मार्च, 1991.

भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 226 और 227—डीपीई और डीआरई परीक्षाओं को पास करने के बाद वेतन वृद्धि का अधिकार–याचिकाकर्ता 1979 में डीपीई परीक्षा में उपस्थित होते हैं लेकिन परिणाम अंततः 1987 में घोषित किया जाता है–याचिकाकर्ता 1981 में डीआरई परीक्षा पास करते हैं–डीपीई परीक्षा पास करना 1978 से संबंधित होगा–याचिकाकर्ता–1981 से प्रभावी रूप से बकाया वेतन वृद्धि के हकदार।

निर्धारित किया गया कि परीक्षा पास करना 1978 की परीक्षा से संबंधित होगा और चूंकि उसने 1981 में डीआरई परीक्षा पास की, सेवा नियमों के तहत, याचिकाकर्ता दोनों परीक्षाएँ पास करने की तारीख से वेतन वृद्धि का हकदार हो जाएगा। चूंकि उसने एक परीक्षा 1978 में और दूसरी 1981 में पास की, वह 1981 से आगे की तारीख से वेतन वृद्धि का हकदार होगा। सरकार का यह आदेश कि याचिकाकर्ता बकाया का हकदार नहीं होगा, यहाँ रद्द किया जाता है। (पैरा 6)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका यह प्रार्थना करते हुए कि: –

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड कृपया बुलाया जाए;

(ii) मैंडेमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा नवंबर, 1978 में ली गई विभागीय पेशेवर परीक्षा का परिणाम घोषित करें;

(iii) मैंडेमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के वेतन को उसे सेवा में शामिल होने की तारीख से प्रभावी रूप से उसके हक के अनुसार वेतन वृद्धि प्रदान करके तय करें और उसे उस खाते पर बकाया वेतन के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अर्जित करें;

(iv) इस मामले की विशेष परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय से यह अनुरोध है कि वह कोई भी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करे जो वह उचित समझता है;

(v) प्रतिवादियों को प्रारंभिक सूचनाएँ जारी करने की प्रक्रिया को छूट दी जाए;

(vi) एनेक्सर की प्रमाणित प्रतियों की फाइलिंग को छूट दी जाए;

(vii) याचिका के खर्चे याचिकाकर्ता को प्रदान किए जाएँ।

याचिकाकर्ता के वकील पी. एस. पटवालिया।

राज्य प्रतिवादी की ओर से एस. के. सूद, एएजी, हरियाणा।

आदेश

1) याचिकाकर्ता विभागीय पेशेवर परीक्षा (DPE) और विभागीय राजस्व परीक्षा (DRE) पास करने के बाद वेतन वृद्धि का हकदार था। याचिकाकर्ता ने 1978 में DPE में उपस्थित हुआ और उस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया क्योंकि उस पर उस परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का आरोप लगा था। जबकि वह मामला लंबित था, याचिकाकर्ता ने 1981 में DRE में उपस्थित हुआ और सफल घोषित किया गया।
2) DPE में अनुचित साधनों का आरोप अगस्त, 1987 में सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णयित किया गया और आरोप वापस लिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता के DPE का परिणाम घोषित किया गया जिसमें वह असफल रहा।
3) जब याचिकाकर्ता को पता चला कि वह उस परीक्षा को पास करने के लिए एक अंक से कम है, उसने अनुदेश, एनेक्सर P/2 के आधार पर उसे एक अनुग्रह अंक देने और उसे पास घोषित करने के लिए राज्य सरकार से प्रतिनिधित्व किया। सरकार ने मामले पर विचार किया। चूंकि मामला देरी हो रही थी, इसलिए वह इस रिट याचिका में इस न्यायालय में आया।
4) मोशन की नोटिस जारी होने के बाद, राज्य सरकार ने मामले पर विचार किया और 4 जनवरी, 1991 को जारी आदेश द्वारा DPE में याचिकाकर्ता को एक अनुग्रह अंक देकर पास घोषित किया। हालांकि, एक शर्त लगाई गई कि उसे पहले की अवधि के लिए बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा और वह आदेश की जारी तारीख यानी 4 जनवरी, 1991 से प्रभावी रूप से वेतन वृद्धि का हकदार होगा। आदेश की प्रति और एक संचार रिकॉर्ड पर रखा गया है।
5) याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता DPE में अपने परिणाम के संबंध में संतुष्ट है लेकिन यह प्रतिवादी थे जो 1978 में या 1981 तक जब तक उसने DRE पास किया था, याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित नहीं करने में गलत थे।
6) हम याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाई गई दलील को स्वीकार करते हैं कि परीक्षा पास करना 1978 की परीक्षा से संबंधित होगा और चूंकि उसने DPE परीक्षा 1981 में पास की, सेवा नियमों के तहत, याचिकाकर्ता दोनों परीक्षाएं पास करने की तारीख से वेतन वृद्धि का हकदार हो जाएगा। चूंकि उसने एक परीक्षा 1978 में और दूसरी 1981

में पास की, वह 1981 से आगे की तारीख से वेतन वृद्धि का हकदार होगा। सरकार का यह आदेश कि याचिकाकर्ता बकाया का हकदार नहीं होगा, यहाँ रद्द किया जाता है।

7) उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को 1981 में उसके दूसरी परीक्षा पास करने की तारीख से सेवा नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्देश जारी किया जाता है। बकाया छह महीने के भीतर आज से भुगतान किया जाए। कोई खर्च नहीं।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।**

**आयुष**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार**
**हिसार, हरियाणा**